



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2559]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 6, 2018/आषाढ़ 15, 1940

No. 2559]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 6, 2018/ASHADHA 15, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2018

**का.आ. 3313(अ).**—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं को सरल बनाता है और पारदर्शिता तथा दक्षता लाता है, और हिताधिकारियों को अपने अधिकारों को सीधे सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है और निर्बाध रीति आधार किसी की पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों के निर्माण की आवश्यकता को दूर करता है;

और भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (जिसे इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के रूप में आयुष्मान भारत कार्यक्रम के अधीन आयुष्मान भारत - राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (जिसे इसके पश्चात योजना कहा गया है) के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) के माध्यम से प्रशासित कर रहा है जिसे विनिर्दिष्ट राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रशासन द्वारा लागू किया गया है;

और इस स्कीम का उद्देश्य देश भर में किन्हीं भी पैनलीकृत अस्पतालों में पारिवारिक फ्लोटर आधार पर प्रति वर्ष पांच लाख रुपये (जिसे इसके पश्चात लाभ कहा गया है) तक की बड़ी संख्या वाली चिकित्सा स्थितियों के लिए नकदी रहित और कागज रहित उपचार में होने वाला व्यय घर के मुखिया और उसके कुटुम्ब के उन सदस्यों (जिसे इसके पश्चात सामूहिक रूप से लाभार्थी कहा गया है), को प्रदान करना है, जैसा भी मामला हो, जो मौजूदा योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं;

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की समेकित निधि से उपगत किया गया व्यय सम्मिलित है;

अतः अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार इस प्रकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या आधार अधिप्रमाणीकरण कराना होगा।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने की वांछा करने वाले किसी भी हिताधिकारी, जिसे आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं किया गया है, को 31 मार्च 2019 तक आधार के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in) पर सूची उपलब्ध] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग को उन हिताधिकारियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिन्हें अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में आधार नामांकन केंद्र नहीं है, तो राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों से समन्वय करते हुए या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु कि जब तक किसी व्यक्ति को आधार न दे दिया जाए, तब तक योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों को प्रसुविधा दी जाएगी, जो निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करते हों: -

- (क) (i) अगर उसे नामांकित किया है या उसके पास आधार नामांकन पहचान पत्र पची है; या
- (ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उनके अनुरोध की एक प्रति, जैसा कि नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और
- (ख) (i) फोटो के साथ बैंक पासबुक या डाकघर पासबुक; या
- (ii) मतदाता पहचान पत्र कार्ड; या
- (iii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या
- (iv) पासपोर्ट; या
- (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या
- (vi) राशन कार्ड; या
- (vii) एमजीएनआरजीएस कार्ड; या
- (viii) किसान फोटो पासबुक; या
- (ix) शासकीय शीर्षनामा पर किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया गया ऐसे व्यक्ति के फोटोयुक्त पहचान पत्र का प्रमाण पत्र; या
- (x) किसी मंत्रालय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट कोई भी अन्य दस्तावेज;
- (ग) अवयस्क के मामले में-
  - (i) अगर उसे नामांकित किया गया है या उसके पास आधार नामांकन आईडी पची है; या
  - (ii) आधार नामांकन के लिए किए गए उनके अनुरोध की एक प्रति, जैसा कि नीचे पैरा 2 के उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट है; तथा
  - (iii) उसके पास संबंध के साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक हो:-
    - (i) उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्म का अभिलेख; (ii) राशन कार्ड; अथवा
    - (iii) पासपोर्ट; अथवा (iv) ईसीएचएस कार्ड; अथवा (v) ईएसआईसी कार्ड; अथवा (vi) सीजीएचएस कार्ड; अथवा
    - (vii) सेना कैटीन कार्ड; अथवा (viii) अन्य कोई सरकारी कुटुंब पात्रता कार्ड; अथवा (ix) अन्य कोई दस्तावेज जो संबंधित मंत्रालय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त दस्तावेजों की विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए संबंधित मंत्रालय अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अंतर्गत हिताधिकारियों को सुविधाजनक तथा परेशानी मुक्त लाभ उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग निम्नलिखित सहित सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा, अर्थात्:-

(1) इस स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षाओं के लिए व्यक्ति विशेष को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार और हिताधिकारियों को व्यक्तिगत नोटिस भी दिया जाएगा तथा यदि उन्होंने पहले से आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं करवाया है तो तारीख 31 मार्च, 2019 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों में नामांकन कराने की सलाह भी दी जा सकती है। उन्हें उपलब्ध स्थानीय नामांकन केंद्रों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि इस स्कीम के अधीन हिताधिकारी ब्लॉक अथवा ताल्लुका अथवा तहसील जैसे आस पास के क्षेत्रों में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण आधार कार्ड के लिए नामांकन नहीं करा पाते तो उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, और हिताधिकारियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ क्षेत्र राज्य प्रशासन द्वारा अथवा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराए गए वेब पोर्टल के माध्यम से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा अन्य विवरण देकर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध रजिस्टर कराएं जैसा कि पैरा 1 के उप पैरा (3) के पहले उपबंधों में विनिर्दिष्ट किया है।

(3) यदि इस स्कीम के अधीन हिताधिकारियों ने आधार के लिए नामांकन करा लिया है, तथापि, किन्हीं कारणों से आधार नंबर प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है तो संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराके यूआईडीएआई नामांकन और अद्यतन क्लाइंट के जरिए “सर्व माई आधार” सुविधा की व्यवस्था करेगा तथा संबंधित हिताधिकारियों से उनके नाम, पते मोबाइल नंबर, अंगुलीछाप तथा अन्य ब्यौरे देकर हिताधिकारी से सहायता प्राप्त ढंग में आधार की तलाश करने का अनुरोध किया जाए तथा साथ ही आधार अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन आधार की खोज करने के लिए ऑपरेटर आधार नंबर को साझा करने, परिचालित या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए हिताधिकारी के आधार की खोज करें।

3. ऐसे सभी मामलों में जहां हिताधिकारियों की खराब बायोमेट्रिक्स के कारण अथवा किसी अन्य कारण के चलते आधार प्रमाणन असफल होता है तो निम्नलिखित अपवाद हैंडलिंग तंत्र को अंगीकार किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) यदि अंगुलीछाप की गुणवत्ता खराब है तो प्रमाणन के लिए आइरिस स्कैन सुविधा का उपयोग किया जाएगा, तत्पश्चात संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग अपनी सेवा वितरण अभिकरण के जरिए लाभ के वितरण के लिए अंगुलीछाप स्कैनरों के साथ-साथ आइरिस स्कैनरों के लिए भी उपबंध करेगा;

(ख) वरिष्ठ नागरिकों या हिताधिकारियों के अंगुलीछाप या आइरिस अधिप्रमाणन में कठिनाई के मामले में, चेहरा अधिप्रमाणन जिसे 1 जुलाई, 2018 से आरंभ किया गया है, का प्रयोग किया जाएगा। राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग उन वरिष्ठ नागरिकों अथवा हिताधिकारियों जिनके लिए प्रमाणन के अन्य प्रकार असफल हो रहे हैं, के लिए यथासंभव चेहरा प्रमाणन की व्यवस्था करेगा।

(ग) अंगुलीछाप या आइरिस या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के मामले सफल नहीं होते हैं जब कभी संभव और स्वीकार्य हो, आधार ओटीपी या टीओटीपी जैसा भी मामला हो, के द्वारा अधिप्रमाणन सीमित समय वैधता को वरीयता दी जाएगी।

(घ) इन सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी प्रमाणन संभव नहीं है, उन वास्तविक आधार पत्र के आधार पर सेवाएं अथवा प्रसुविधाएं दी जा सकती हैं जिनकी प्रमाणिकता की जांच आधार पत्र पर मुद्रित कोड के जरिए की जा सकती है। इसके लिए संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी विभाग को आधार पत्र अथवा ई-आधार पर मुद्रित क्यूआर कोड को पढ़ने के लिए सेवा वितरण केंद्रों पर क्यूआर कोड रीडर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे ऑफ लाइन तरीके से आधार कार्ड की प्रमाणिकता की जांच हेतु मंजूरी प्राप्त होती है। यह क्यू आर कोड यूआईडीएआई द्वारा विकसित सुरक्षित क्यू आर कोड रीडर के जरिए पढ़ा जाएगा क्योंकि यह आधार धारक का डिजिटल तौर पर हस्ताक्षरित ब्यौरा उपलब्ध कराता है। ऐसे सभी मामलों में सभी प्रसुविधा या सेवाएं अपवाद हैंडलिंग रजिस्टर मोड में इस प्रयोजनार्थ किए गए लेन-देन को उपयुक्ततः दर्ज करने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी, जिनकी समीक्षा तथा लेखा परीक्षा आवधिक तौर पर संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। इस रजिस्टर का रख-रखाव तथा आवधिक निरीक्षण अपवाद हैंडलिंग तंत्र का एक आवश्यक घटक होगा।

4. यह अधिसूचना जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त की जाएगी।

[फा. सं. एस-12012/40/2016-आरएसबीवाई दिनांक 04.07.2018]

आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2018

**S.O. 3313(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the programme of Ayushman Bharat – National Health Protection Mission (AB-NHPM) (hereinafter referred to as the Scheme) under the Ayushman Bharat program as Centrally Sponsored Scheme through National Health Agency (NHA), which is implemented by the specified State Governments and Union Territory Administrations;

And whereas, the Scheme aims at providing cashless and paperless hospitalisation expenses for a large number of medical conditions, up to rupees five lakhs per annum on family floater basis at any empanelled hospitals across the country (hereinafter referred to as the benefits) to the head of the household and his or her family members, as the case may be (hereinafter collectively referred to as the beneficiaries), who meet the eligibility criteria as defined in extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) A beneficiary eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who is not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar by 31<sup>st</sup> March 2019 provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the Said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)] for Aadhaar enrolment.
- (3) As per regulation 12 of The Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrars themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individuals, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) if he or she or has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or  
(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or  
(ii) Voter ID Card; or  
(iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or  
(iv) Passport; or  
(v) Driving licence issued by The Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or  
(vi) Ration Card; or

- (vii) MGNREGS Card; or
- (viii) Kisan Photo Passbook; or
- (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
- (x) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or the Union Territory Administration;
- (c) in case of minors -
  - (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
  - (ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and
  - (iii) any one of the following documents as proof of relationship:-
    - (i) Birth Certificate or Record of Birth issued by appropriate Government Authority; or (ii) Ration Card; or (iii) Passport; or (iv) ECHS Card; or (v) ESIC Card; or (vi) CGHS Card; or (vii) Army Canteen Card; or (viii) any Government Family Entitlement Card; or (ix) Any other document as specified by the Ministry or the State Government or the Union Territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry or the State Government or the Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31<sup>st</sup> March, 2019, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) in case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned officials specifically designated by the State Government or the Union Territory Administration or through the web portal provided for the purpose.

(3) in case, the beneficiaries under the Scheme have enrolled for Aadhaar, however, are not able to produce Aadhaar number for any reason whatsoever, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration shall provide “Search My Aadhaar” facility through UIDAI’s Enrolment and Update Client by facilitating Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to search their Aadhaar in assisted mode by giving their names, addresses, mobile numbers, finger prints and other details, with the operator required to search beneficiary’s Aadhaar, subject to the provisions of the Aadhaar Act and regulations made there under with respect to restriction on sharing, circulating or publishing of Aadhaar number .

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely :-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration shall through its service delivery agency make provisions for iris scanners along with finger print scanners for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of difficulty in finger prints or iris authentication of senior citizens or the beneficiaries, face authentication, which may be launched from 1<sup>st</sup> July 2018, shall be used. The concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Governments or Union Territory Administration shall make arrangements for face authentication wherever feasible, for those senior citizens or those beneficiaries whose other modes of authentication fail.

(c) in case of biometric authentication through finger prints or iris or face authentication is not successful, whenever feasible and admissible, authentication by Aadhaar OTP or as the case may be TOTP, with limited time validity shall be preferred;.

(d) in all other cases where biometric or OTP authentication is not possible, services or benefits may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. For this, the concerned Department responsible for implementation of the Scheme

in the State Government or the Union Territory Administration shall provide QR code readers at point of service delivery to read QR code printed on Aadhaar letter or E- Aadhaar which allows verifying the authenticity of Aadhaar card in an offline manner. This QR code shall preferably be read through Secure QR code reader developed by UIDAI as it provides digitally signed details of Aadhaar Holder. In all such cases the benefit or service may be provided after duly recording the transaction in the exception handling register made for this purpose, which is to be reviewed and audited periodically by the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or the Union Territory Administration. Maintenance of these register and periodic inspection will be an essential component of exceptional handling mechanism.

4. This notification shall come into force effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. S-12012/40/2016-RSBY Dated 04.07.2018]

ALOK SAXENA, Jt. Secy.